



Press Release

7th July, 2016

FINANCE MINISTER JAITLEY RELEASED LESS CASH CAMPAIGN ROAD MAP OF CAIT 15TH AUGUST TO BE OBSERVED AS LESS CASH DAY

Union Finance Minister Mr. Arun Jaitley yesterday released 'less cash campaign road map' of the Confederation of All India Traders (CAIT) which has launched a nationwide campaign for promotion of usage of digital payments across the Country in line with call of Prime Minister Shri Narendra Modi for converting Indian economy into a cash less economy.

The CAIT has decided to conduct an aggressive campaign for next 40 days while observing forthcoming 15th August as Less Cash Day all over the Country. During its campaign, the CAIT will organise Seminars, Conferences, Round Table and Workshops in different states of the Country emphasizing the need of adoption of electronic payments as mode of payment among trading community. The copies of CAIT's less cash roadmap will be submitted to Union Ministers, Chief Ministers, Finance Ministers of all States, Senior Officials of Union & State Governments, Leaders of all political parties and MPs of both Lok Sabha & Rajya Sabha. The CAIT will also use social media as a tool for percolation of the campaign message down the line across the Country. Beside traders, the CAIT also intend to rope in Farmers, Transporters, SMEs, Hawkers, Consumers, Self Employed Groups, Women Entrepreneur & other sections in its campaign.

While releasing the less cash road map of CAIT, Mr. Jaitley stressed the need of eradication of shadow economy and opined that more usage of digital payments will bring more transparency & accountability and will lead to further growth in GDP and economy. Black Money is a plague for the economy and needs to be weeded out from the system. He called upon the people to avail scheme of the Union Government for voluntary disclosure. He complimented CAIT for conducting such a campaign which will certainly support move of the Government to promote usage of electronic payments. It is noteworthy to mention that even in proposed GST Model Bill, it is provided that all taxes will be paid through either Debit/Credit Card or through NEFT or RTGS and therefore adoption of electronic payments by trade & commerce in the Country will pave a way for easy compliance of GST taxation system as well.

Mr. B. C. Bhartia, National President & Mr. Praveen Khandelwal, Secretary General of the CAIT said that "we are committed to pursue our vision for promotion of Less Cash system in trade & commerce which will enable India to see double digit growth, it is critical for its largest community of self-employed, small & medium business owners to adopt and use modern means of technology". There are about 5.77 crore small businesses in the Country. The promotion of less cash campaign will not only includes allowing consumers the convenience of paying through electronic means i.e. credit/debit cards and wallets, but also critical investments in promoting businesses online. This not only allows a wider market access to traders but also allows consumers to mine price competitive, absolute quality products & services. However, the Government should make specified rules & regulation for e commerce business in India and on the other hand must bring a policy to provide incentives like tax benefits etc. for encouraging people to use electronic payments-added both trade leaders.

According to CAIT's less cash roadmap, benefits of a less cash society are well known in the form of its positive effects on economic growth as a result of increased trade and the opportunities to promote financial inclusion. However, despite these known advantages, cash still dominates in India. Continued high cash usage has its ill effects in the form of shadow economy which hurts the ability of governments to efficiently collect tax revenues. Additionally, the rise of cyber-crime and growing concerns about the ability of governments to look through digital records adds to the unwillingness of many with criminal intent to let go of cash. While benefits of digital payments are widely understood, the growth in acceptance infrastructure has not kept pace with the growth in cards.

The report concludes with highlighting efforts to promote digital payments though primary focus on a free market, payment-neutral approach to changing the perception amongst consumers and merchants that cash is not less costly than digital payments, and everyone pays a price for cash usage.

This follows CAIT's recent initiatives wherein both Shri. Amitabh Kant, CEO – NITI Aayog and Shri. Ramesh Abhishek, Secretary – DIPP at an event organized by CAIT last month emphasized that the community of small merchants and traders needed to adapt with today's times and embrace online marketplaces and facilitate digital payments.

For more details, please contact CAIT Secretary General Mr. Praveen Khandelwal at +91-9891015165-9310199771



प्रेस विज्ञप्ति

7 जुलाई, 2016

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किया कैट का कम नकद अभियान रोडमैप

15 अगस्त को मनाया जायेगा कम नकद दिवस

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा शुरू किये गए "नकद कम अभियान रोडमैप" को कल अपने कार्यालय में जारी किया ! प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नकदरहित अर्थव्यवस्था को अपनाने के आवाहन के समर्थन में कैट ने देश भर में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है !

अगले 40 दिनों में कैट देश के सभी राज्यों में इस अभियान को जोर-शोर से चलाएगा और आगामी 15 अगस्त "कम नकद दिवस" के रूप में मनाया जायेगा ! अपने अभियान के दौरान कैट देश भर में कांफ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, गोल मेज़ सम्मेलन आदि आयोजित कर लोगों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अपनाने के लिए प्रेरित करेगा ! कैट के कम नकद अभियान रोड मैप की प्रति केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री को दिए जाएंगे ! इसके अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रमुख नेता तथा लोक सभा और राज्य सभा के सभी सांसदों को भी दी जाएँगी ! इस अभियान को मुकम्मल तौर पर चलाने के लिए कैट सोशल मीडिया का भी पूरा उपयोग करेगी ! व्यापारियों के अलावा कैट किसानों, ट्रांसपोर्टर, लघु उद्योग, हॉकर्स, उपभोक्ता, स्वयं उद्यमी, महिला उद्यमी सहित अन्य वर्गों को भी इस अभियान से जोड़ेगी !

कैट के कम नकद अभियान रोड मैप को जारी करते हुए श्री जेटली ने सामानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने का आव्हान किया और कहा की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पारदर्शिता लाएगा और व्यवस्था को भी उत्तरदायी बनाएगा ! उन्होंने कहा की काला धन अर्थव्यवस्था के लिए एक प्लेग के समान है जिसको समाप्त किया जाना देश हित में है ! उन्होंने कहा की केंद्र सरकार द्वारा काले धन को स्वैच्छिक सरेंडर किये जाने वाली योजना का लाभ सभी को उठाना चाहिए ! कैट के अभियान को बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा की सभी वर्गों को अपने यहाँ इस तरह के अभियान चलाने का आग्रह किया ! जातव्य है की जीएसटी के मॉडल बिल के प्रावधान के अनुसार कर की अदायगी केवल डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक ट्रांसफर से ही होगी, इस दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भविष्य में कर व्यवस्था के पालन में बड़ी भूमिका निभाएगा !

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भर्तियां एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने कहा की देश की अर्थव्यवस्था में 5.77 करोड़ छोटे व्यवसायों का बड़ा योगदान है और इस वर्ग में यदि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को दो अंकों तक जाने में कोई देर नहीं लगेगी लेकिन उसके लिए व्यापारिक व्यवस्था को सरल बनाने की पहल सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है ! इ कॉमर्स के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान आवश्यक प्रतीत होते हैं लेकिन सरकार को इसके लिए स्थापित नियम एवं कानून बनाने जरूरी हैं जिससे इ कॉमर्स बाजार का दुरुपयोग रोका जा सके वहीं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए सरकार व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने पर करों में छूट जैसे लाभ दिए जाएँ !

कैट ने अपने कम नकद अभियान रोड मैप में कहा है की इलेक्ट्रॉनिक भुगतान निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक हैं और व्यापार में वृद्धि तथा वित्तीय समावेश को बढ़ावा देते हैं लेकिन इस सबके बावजूद अभी तक देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का माहौल बन नहीं पाया है क्योंकि पूर्व सरकारों द्वारा इस ओर कोई ठोस प्रयास नहीं किये गए जिसके चलते नकद का चलन बहुत अधिक है जो सामानांतर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और सरकार की कर एकत्र करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है ! देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को प्रेरित करने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है और सरकार को इसके लिए सभी वर्गों से बातचीत करते हुए एक समग्र नीति बनानी होगी जिसमें काफी हद तक प्रशासनिक सुधार भी करने होंगे ! कैट ने अपने रोडमैप में ऐसे सभी आवश्यक कदमों का हवाला भी दिया है !

